

वी. पेचिमुत्तु

बनाम

गोवरामल

अगस्त 1, 2001

[वी. एन. खरे और रूमा पाल, जे. जे.]

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963: धारा 16 और 20।

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए विशिष्ट अनुकंपा का दावा समझौता-मालिक ने अपनी अचल संपत्ति खरीदार को बेच दी- खरीदार 5 साल बाद एक निश्चित राशि के लिए मालिक को संपत्ति वापस बेचने के लिए सहमत हो गया- मालिक अनुबंध के अपने हिस्से की अनुकंपा करने के लिए तैयार था और विक्रेता को संपत्ति को फिर से देने के लिए कहा।

विशिष्ट अनुपालना के लिए दायर किया गया मुकदमा- निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया- पहली अपील अदालत ने डिक्री की पुष्टि की- हालांकि, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में, यह मानते हुए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया कि पुनः खरीद समझौता एक विशेषाधिकार या रियायत थी; और यह कि समझौता सामान्य नहीं था।

समझौता की शुद्धता-आयोजित: पुनः खरीद के समझौते और खरीद के सामान्य समझौते के बीच कोई अंतर नहीं है- समझौता अभी भी अचल संपत्ति की बिक्री के लिए एक समझौता बना हुआ है और इसे सामान्य समझौते से संबंधित उसी कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए- मालिक समझौते के विशिष्ट अनुपालना का हकदार है- इसलिए, उच्च न्यायालय ने विशिष्ट अनुपालना के आदेश को उलटने में गलती की।

विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री- वाद संपत्ति की कीमत में वृद्धि, पहली बार विशिष्ट निष्पादन की डिक्री देते समय वाद संपत्ति की कीमत में वृद्धि, राहत देने से इनकार करने में एक प्रासंगिक कारक हो सकता है- लेकिन जब आदेश निचली अदालत द्वारा पारित किया जाता है और पहले द्वारा पुष्टि की जाती है अपील न्यायालय ऐसा कारक दूसरी अपील में प्रासंगिक नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: धारा 100- दूसरी अपील- तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष- दूसरी अपील में पलटाव- कार्यवाही के किसी भी चरण में नहीं उठाए गए बिंदु पर अभिनिर्धारित, उच्च न्यायालय को दूसरी अपील के स्तर पर एक असंगत तर्क को उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी- इसलिए, तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को दरकिनार करते हुए-

अनुबंध अधिनियम, 1872: अनुबंध-पुनः खरीद के विकल्प के साथ समझौता और सामान्य समझौता-मालिक द्वारा खरीदार को बेची गई संपत्ति के बीच का अंतर- इसके बाद, खरीदार एक निश्चित मूल्य पर संपत्ति को मालिक को वापस बेचने के लिए सहमत हो गया।

राशि-आयोजित, बाद का समझौता एक सामान्य समझौता है और नियंत्रित होता है सामान्य समझौते से संबंधित उसी कानून द्वारा।

शब्द और वाक्यांश:

" विशेषाधिकार "और" रियायत "-- का अर्थ

अपीलार्थी एक निश्चित अचल संपत्ति का स्वामी था, जो उत्तरदाता को बेच दिया गया। बाद के समझौते से प्रत्यर्थी सहमत हो गया 5 साल के बाद एक निश्चित राशि के लिए संपत्ति को अपीलार्थी को वापस बेचना। इसके बाद पाँच वर्ष की समाप्ति पर अपीलार्थी ने बार-बार मांग की प्रत्यर्थी उसे समझौते के संदर्भ में संपत्ति को फिर से देने के लिए कहता है। अपीलार्थी ने अपनी भूमिका निभाने के लिए अपनी तैयारी और इच्छा भी व्यक्त की अनुबंध से। लेकिन उत्तरदाता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद अपीलार्थी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमा दायर किया जो डिक्री किया गया था। पहला अपीलीय न्यायालय कुछ संशोधनों के साथ डिक्री की पुष्टि की। लेकिन उच्च न्यायालय, दूसरे में सिविल

प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत अपील वाद के निर्माण पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष कि पुनः परिवहन मूल मालिक को दी गई रियायत या विशेषाधिकार था और यह कि, इसलिए, न केवल इस तरह के समझौते की शर्तें सख्ती से होनी चाहिए अपीलार्थी के विरुद्ध समझा जाता है, लेकिन इसके लिए "सामान्य" समझौतों के विपरीत भी अधिकार लागू किया जाएगा और कि अपीलार्थी न्यायालय में नहीं आया था साफ हाथों से। इसलिए यह अपील की गई है।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठा:

क्या सिविल संहिता की धारा 100 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतगठ उच्च न्यायालय समवर्ती निष्कर्ष को दरकिनार करने में उचित था?

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1. यह कानून का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है कि बिक्री का प्रत्येक समझौता जिसके द्वारा मूल मालिक संपत्ति को वापस खरीदने के लिए सहमत होता है, एक विशेषाधिकार या ऐसे मालिक को दी गई रियायत है। एक विशेषाधिकार को एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त एक विशेष और विशिष्ट लाभ या लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है, और विशेषाधिकार के रूप में रियायत, खरीदने या फिर से खरीदने का एक विकल्प ऐसा विशेषाधिकार या रियायत है। [208 - ए]

के. सिमरथमुल बनाम। नंजलिंगैया गौडर, आकाशवाणी (1963) एस. सी. 1182, के आधार पर।

षण्मुघम पिल्लई बनाम अन्नलक्ष्मी अम्मल, आकाशवाणी (1950) एफ. सी. 38; हसम नूरानी मलक बनाम मोहन सिंह, आकाशवाणी (1974) बम। 136 और एस. शंकरन बनाम एन. जी. राधाकृष्णन, (1994) 2 एल. डब्ल्यू. 642, संदर्भित।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 6 वीं संस्करण, संदर्भित।

1.2. अपनी प्रकृति से एक विकल्प पूरी तरह से इच्छा पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति को विकल्प दिया गया है। विकल्प देने वाले व्यक्ति द्वारा उसे व्यायाम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। यह इस एक-पक्षीयता के कारण है या "एकतरफा" के रूप में यह था कि अधिकार का कड़ाई से अर्थ लगाया गया है और "पट्टे के नवीनीकरण के लिए, या संपत्ति की खरीद या पुनर्खरीद के लिए एक विकल्प, सभी मामलों में उद्देश्य के लिए सीमित समय के भीतर सख्ती से प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। "

[208 - बी-सी]

हैल्सबरीज लॉज ऑफ़ इंग्लैंड, थर्ड एडन। खण्ड. 3 कला. 281, पी। 165 , संदर्भित किया गया।

1.3. अपीलार्थी के पास संपत्ति के पुनः हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है। एक विकल्प की विशेषताएँ। [209 - एफ]

षण्मुघम पिल्लई बनाम अन्नलक्ष्मी, आकाशवाणी (1950) एफ. सी. 38 और के. सिमरथमुल बनाम नंजलिंगैया गौडर, ए. आई. आर. (1963) एस. सी. 1182 का उल्लेख किया गया।

2.1. दूसरी ओर, बिक्री और खरीद के लिए एक समझौता, अधिक सरल एक पारस्परिक व्यवस्था है जो दोनों पर दायित्वों और लाभों को लागू करती है पक्षकार और दोनों के उदाहरण पर प्रवर्तनीय है। इस तरह के अनुबंध की व्याख्या अनुबंध के कानूनों द्वारा नियंत्रित की जाएगी पारस्परिक वादों का निष्पादन। [208 - डी]

2.2. चाहे कोई समझौता खरीदने का विकल्प हो या "साधारण"। समझौता इसके प्रावधानों की व्याख्या पर निर्भर करेगा। कभी-कभी विकल्प स्पष्ट रूप से और शर्तों में दिया जाता है। अन्य में अधिकार निहित हो सकता है। इस प्रकार जब कोई समझौता यह प्रदान करता है कि बिक्री प्राप्त करने का अधिकार खरीदार द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन है, तो समझौता होगा प्रभाव खरीद का एक विकल्प होगा, क्योंकि खरीद का अधिकार केवल मालिक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के स्वैच्छिक प्रदर्शन पर ही प्राप्त होगा। विक्रेता खरीदार द्वारा शर्तों के प्रदर्शन को मजबूर नहीं कर सकता है।

फिर अनुबंध को विशेष रूप से निष्पादित करने के लिए कहें। [208 - ई-एफ }

2.3 . बिक्री के लिए एक समझौते की तुलना में केवल तथ्य को एक पुनः विवरण के रूप में वर्णित किया गया है तथ्य यह है कि जो संपत्ति बेची जानी है वह व्यक्ति द्वारा खरीदी जा रही थी जो मालिक हुआ करता था। के बीच कोई तार्किक अंतर नहीं निकाला जा सकता है पुनः खरीद के लिए समझौता और खरीद का एक सामान्य समझौता सिर्फ इसलिए क्योंकि विक्रेता मूल खरीदार होता है और खरीदार होता है मूल विक्रेता होना। समझौता बिक्री के लिए एक समझौता बना हुआ है अचल संपत्ति और कानून के समान प्रावधानों द्वारा शासित होनी चाहिए। [210 - डी-ई]

3. तथ्य यह है कि अपीलार्थी अदालत में क्लीन हाथ के साथ नहीं आया था। मेरे मंच पर प्रतिवादी द्वारा उठाया गया मुद्दा नहीं था और न ही कोई मुद्दा था, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में तर्क दिया गया है, विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष। इसके अलावा, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से कहा गया था, यह अभिनिर्धारित नहीं किया था कि तथ्य की अदालत ने स्पष्ट रूप से भुगतान के सवाल में जाने से इनकार कर दिया बिक्री विलेख के तहत प्रत्यर्थी द्वारा संतुलन विचार क्योंकि उसने अभिनिर्धारित किया, ठीक है, कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में

अदालत का संबंध नहीं था। क्या मूल बिक्री विलेख के तहत कोई प्रतिफल का भुगतान किया गया था प्रत्यर्थी के पक्ष में अपीलार्थी द्वारा निष्पादित। [212 - डी-एफ]

कोम्मिसेट्टी वेंकट सुब्बरैया बनाम। करमसेट्टी वेंकटेश्वरलू, आकाशवाणी (1971) एपी 279 और बुचिराजू बनाम। श्री रंगा सत्यनारायणा, आकाशवाणी (1967) एपी 69, संदर्भित को।

4. उच्च न्यायालय ने तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को बाधित करने में गलती की केवल प्रत्यर्थी द्वारा नहीं उठाए गए मुद्दे पर वाद के निर्माण पर कार्यवाही के किसी भी चरण में। उच्च न्यायालय को नहीं करना चाहिए परिस्थितियों ने प्रतिवादी को दूसरी अपील के चरण में एक असंगत तर्क उठाने की अनुमति दी है। [211 - बी; 211-ई]

सैयद दस्तगीर बनाम। टी. आर. गोपालकृष्ण शेट्टी, [1999] 6 एस. सी. सी. 337 और मोतीलाल जैन वी। रामदासी देवी, ए. आई. आर. (2000) एस. सी. 2048 का उल्लेख किया गया है।

5. जहाँ न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि इसके लिए डिक्री दी जाए या नहीं। पहली बार विशिष्ट प्रदर्शन के लिए, भूमि की कीमत में वृद्धि, जिसे व्यक्त करने के लिए सहमति दी गई थी, विशिष्ट अनुपालना की राहत को अस्वीकार करने में एक प्रासंगिक कारक हो सकता है।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि की गई। इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय इस मामले में सही था।

विशिष्ट निष्पादन के आदेश को उलटना। मूल्य में वृद्धि भूमि एक प्रासंगिक कारक नहीं है। [212 - एच; 212-ए]

के. एस. विद्यानाडम बनाम वैरवन। [1997] 3 एस. सी. सी. 1, लागू नहीं होता। सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 336 1997 मद्रास उच्च न्यायालय के 29.1.96 दिनांकित निर्णय और आदेश से 1982 के एस. ए. सं. 1997 में।

अपीलार्थी की ओर से के. राम कुमार और बी. श्रीधर। आर. सुंदरवर्धन, आर. एन. केशवानी, संजय कुनूर और रामलाल रॉय उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय रूमा पाल, जे. द्वारा दिया गया था।

यह अपील उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेप आदेश के विरुद्ध है।

दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने विशिष्ट अनुपालना के आदेश को दरकिनार कर दिया। विचारण और प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों द्वारा अपीलार्थी को दिया गया विशिष्ट अनुपालना की डिक्री। मुद्दा यह है कि क्या

उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया था।

आइए तथ्यों पर विचार करें।

अपीलार्थी कुछ संपत्ति का स्वामी था। संपत्ति थी किराए पर लिया और गिरवी रखा। 2 मई 1973 के एक विलेख द्वारा, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को संपत्ति 20,000 रुपये की राशि में बेच दी। इस राशि में से रु 15,005 अपीलार्थी के बंधक ऋण का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा संपत्ति के बंधककर्ता को भुगतान किया जाना था। बिक्री विलेख में दर्ज किया गया है कि रुपये की शेष राशि 4,995 अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से संपत्ति के किरायेदारों द्वारा किए गए अग्रिम किराए के पुनः भुगतान के लिए प्राप्त किया गया था ताकि प्रत्यर्थी को खाली कब्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

4 मई 1973 को दोनों प्रकाशों के बीच एक अलग समझौता किया गया था। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी जिसके द्वारा प्रत्यर्थी निष्पादन की तारीख से 5 वें वर्ष के बाद अपीलार्थी को संपत्ति वापस बेचने के लिए सहमत हुआ समझौते की राशि और छठे वर्ष की समाप्ति से पहले रु. 19,990। रु. 20,000 रुपये की कम राशि Rs 10 अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को अग्रिम रूप से भुगतान किया जाता है। यह वह समझौता है जो हमारे समक्ष मुकदमे

का विषय है और जिसे इसके बाद 'समझौता' के रूप में संदर्भित किया जाता है। बिक्री विलेख और समझौता दोनों 13 जून 1973 को पंजीकृत किए गए थे। बिक्री के बाद, प्रत्यर्थी ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया और तब से संपत्ति के कब्जे में है। यह अपीलार्थी का मामला है कि 5 वर्षों के बाद, अपीलार्थी ने व्यक्तिगत रूप से और उनके मध्यस्थों के माध्यम से बार-बार मांग की प्रत्यर्थी से बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए कहा। रुपये की पूरी राशि प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी का खर्च। 19,990 प्रतिवादी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अंततः, अपीलार्थी ने एक नोटिस भेजा 6 फरवरी 1979 को उनके वकील ने प्रतिवादी से जवाब भेजने के लिए कहा। निर्दिष्ट करते हुए सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिनों के भीतर जिस तारीख को प्रत्यर्थी रुपये का प्रतिफल प्राप्त करने के बाद उप-पंजीयक कार्यालय में बिक्री विलेख निष्पादित करेगा। 19,990 और अधिकार देने के लिए उसी स्थिति में संपत्ति जिसमें इसे बेचा गया था। यह था नोटिस 7 फरवरी 1979 को प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त। 16 फरवरी 1979 को, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की मांग का खंडन करते हुए जवाब दिया और दावा किया कि रुपये से अधिक राशि 20,000 क्योंकि उसने रुपये की एक और राशि का भुगतान किया था। 1448 गिरवीदार को उस राशि के अलावा जो वह बिक्री विलेख के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी और उसने रुपये का खर्च भी किया था। 700 बन्धक के साथ मुकदमे के संबंध में।

प्रत्यर्थी के अनुसार, उसने रुपये की अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया था। 3,000 प्रत्यर्थी को और यह कि, इसलिए, अपीलार्थी संपत्ति के पुनः हस्तांतरण के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए बाध्य था।

मार्च, 1979 में अपीलार्थी ने समझौते के विशिष्ट निष्पादन का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया। शिकायत में तथ्यों का वर्णन करते हुए, अपीलार्थी ने यह भी कहा कि प्रत्यर्थी ने वास्तव में अपीलार्थी को रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया। 4,995 जैसा कि बिक्री विलेख में कहा गया है रु. की राशि। 2,500 प्रत्यर्थी द्वारा सीधे संपत्ति के किरायेदार को भुगतान किया गया था लेकिन रुपये की शेष राशि 2495 अपीलार्थी को कभी भुगतान नहीं किया गया। अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि उसे रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ा 2,000 गिरवीदार को क्योंकि प्रत्यर्थी ने समय पर गिरवीदार के बकाया का भुगतान करने में चूक की थी। अपीलार्थी ने आगे कहा कि वह संपत्ति के पुनः हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से ही समझौते के अपने हिस्से का पालन करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक था, अर्थात्, 3.5.1978 और प्रत्यर्थी से व्यक्तिगत रूप से और मध्यस्थों के माध्यम से बार-बार मांग कर रहा था कि वह अपीलार्थी के खर्च पर बिक्री विलेख को निष्पादित करे। 19,990. प्रत्यर्थी के पत्र में इनकार किया गया और यह दोहराया गया कि अपीलार्थी हमेशा तैयार और इच्छुक था 4 मई 1973 के समझौते के अपने हिस्से का पालन

करने के लिए और यह कि वह रुपये की बिक्री विचार की शेष राशि का भुगतान करने के लिए तैयार था। 19,990 और दाखिल करने की तारीख को भी अपीलार्थी को बिक्री करने के लिए खर्च सूट से। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के संबंध में बहुत अधिक लाभ का दावा किया 3 मई 1978 के बाद मुकदमे की संपत्ति का कब्जा जारी रखा और साथ ही ऋण भी बंधक और रुपये की राशि 3,000 खर्चों की ओर जो होगा वाद सम्पत्तियों की मरम्मत के लिए अपीलार्थी द्वारा किया गया व्यय। तैयारी और 4 मई 1973 के समझौते को पूरा करने के लिए अपीलार्थी की इच्छा को शिकायत के पैराग्राफ 11 में फिर से दोहराया गया था। अपीलार्थी ने अंततः एक फरमान के लिए प्रार्थना की: 'प्रतिवादी को बिक्री विलेख निष्पादित करने का निर्देश देना वादी के पक्ष में वाद संपत्ति के लिए वादी के खर्च पर रुपये का विचार। 20,000 बिक्री शेष राशि प्राप्त करने के बाद वादी से विचार (इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित)

एक निर्दिष्ट तिथि के भीतर और यदि प्रतिवादी बिक्री को निष्पादित करने में विफल रहता है निष्पादित किए जाने के लिए उपरोक्त बिक्री विलेख का निर्देश देने वाला विलेख प्रतिवादी की ओर से न्यायालय द्वारा।

अपने लिखित बयान में, प्रतिवादी ने निष्पादन से इनकार नहीं किया समझौता लेकिन इस बात से इनकार करता है कि अपीलार्थी किसी भी राशि के लिए किसी भी क्रेडिट का हकदार था। दूसरी ओर प्रत्यर्थी के

अनुसार रु 3,000 अपीलार्थी द्वारा देय था, एक दावा जिसके लिए एक मुकदमा दायर किया गया है और डिक्री प्राप्त की गई है। प्रत्यर्थी ने यह भी दावा किया कि उसे रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा 1448.75 गिरवीदार को और रुपये खर्च करने पड़े। 3,000 सूट संपत्ति को अच्छी स्थिति में रखने के साथ-साथ कुल रुपये के आकस्मिक और 700 कानूनी खर्चों के लिए भुगतान करना। यह कहा गया था कि अपीलार्थी मौखिक रूप से रुपये 30,000 में पुनः परिवहन के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए सहमत हो गया था और जैसा कि प्रतिवादी ने 30,648 रुपये का भुगतान किया था, अपीलार्थी को या उसके कारण, अपीलार्थी अपने प्रत्यर्पण के अधिकार को लागू करने का हकदार नहीं था। प्रत्यर्थी ने विवाद किया कि अपीलार्थी भुगतान करने के लिए तैयार था या 20,000 रुपये की राशि जमा करें और अपीलार्थी को साबित करने के लिए ऐसा करने के लिए कहा उनकी सत्यनिष्ठा। लिखित बयान के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा किसी भी तरह के लाभ का भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं था।" दूसरी ओर वादी 27,648 रुपये जमा करने और भुगतान करने के लिए बाध्य है। (पुनः परिवहन के लिए) जो दावा करता है अधिनियम में (वास्तव में) उसे दोनों के बीच मौखिक समझौते के अनुसार त्याग करना चाहिए। वादी और यह प्रतिवादी जैसा कि पहले ही यह लिखित बयान दे चुके हैं अपीलार्थी के पक्ष में मुकदमा चलाया गया। यह ऐसा प्रतीत होता है

कि प्रत्यर्थी ने एक मौखिक समझौते के मामले को रद्द कर दिया था मुकदमे की। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने भी अपीलार्थी के मामले को खारिज कर दिया जहाँ तक उसने विभिन्न राशियों के लिए श्रेय का दावा किया था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि प्रतिवादी बिक्री विलेख के तहत भुगतान करने में विफल रहा था। हालांकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी का अधिकार था रु. 23, 448.75 राशि के भुगतान पर दूसरे समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तरदाता को अधीनस्थ न्यायाधीश ने उस हद तक प्रत्यर्थी के इस दावे को स्वीकार कर लिया कि प्रत्यर्थी के पास मूल राशि रु. 20,000 , रुपये के अलावा अतिरिक्त राशि 3,448.75 का भुगतान किया। अपीलार्थी को या अपीलार्थी का खाता जिसे पुनः परिवहन की लागत में जोड़ा जा सकता है। के द्वारा डिक्री अपीलार्थी को 23,448.75 रुपये की राशि जमा करने की आवश्यकता थी। डिक्री का लाभ उठाने के लिए 7 मई 1981 को या उससे पहले अपीलार्थी ने 23,448.75 रुपये की राशि जमा की।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों ने इसके खिलाफ अपीलों को प्राथमिकता दी

अधीनस्थ न्यायाधीश का निर्णय। अपीलों पर समान रूप से सुनवाई की गई। इससे पहले जिला न्यायाधीश, अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था केवल रु. 12,495 प्रत्यर्थी

द्वारा भुगतान नहीं की गई राशि का श्रेय लेने के बाद बिक्री विलेख या उसके द्वारा किए गए खर्चों के अंतर्गत। दूसरी ओर उत्तरदाता हाथ ने तर्क दिया कि अपीलार्थी विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री का हकदार नहीं था और यह कि अधीनस्थ न्यायाधीश को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि अपीलार्थी रुपये की अतिरिक्त 3,000 राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। कथित तौर पर प्रतिवादी द्वारा वाद संपत्ति में विभिन्न सुधार करने में खर्च किया गया। जिला न्यायाधीश निम्नलिखित रूप में विचार के लिए बिंदुओं को तैयार किया:

(i) क्या वादी विशिष्ट राहत का हकदार है।

प्रदर्शन?

(ii) वादी द्वारा देय बिक्री प्रतिफल क्या है?

पुनः परिवहन विलेख का निष्पादन?

जिला न्यायाधीश ने कहा कि पक्ष समझौते की शर्तों से बंधे थे जो एक पंजीकृत दस्तावेज था और जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था या किसी भी तरह से परिवर्तित किया गया। उन्होंने नोट किया कि समझौते के संदर्भ में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को उस तारीख और समय को निर्दिष्ट करने के लिए नोटिस दिया था जिस पर प्रतिवादी आएगा और 19,990 रुपये का विचार प्राप्त करने के बाद संबंधित उप-पंजीयक के

कार्यालय में बिक्री को निष्पादित करेगा और संपत्तियों का कब्जा अपीलार्थी को सौंप दें। यह नोट किया गया था कि नोटिस अपीलार्थी ने यह दावा नहीं किया था कि वह इससे कुछ भी कम भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था कि प्रत्यर्थी राशि से अधिक कुछ भी पाने का हकदार नहीं था समझौते के तहत तय किया गया विचार और जैसा कि प्रतिवादी ने किया था बंधक ऋण का निर्वहन करने के लिए किया गया जो वह किसी भी ऋण का दावा करने की हकदार नहीं थी। अतिरिक्त भुगतान जो बंधककर्ता को किया गया हो सकता है। किसी भी मामले में, प्रत्यर्थी ने न तो कोई जवाबी दावा किया था और न ही मुकदमा दायर किया था और न ही भुगतान किया था ऐसे दावे के संबंध में कोई भी न्यायालय शुल्क। जिला न्यायाधीश ने भी खारिज कर दिया प्रत्यर्थी का मामला कि उसने रुपये की राशि का भुगतान किया था। 4495 किरायेदारों के लिए संपत्ति। इन परिस्थितियों में, जिला न्यायाधीश ने अपीलार्थी को निर्देश दिया 19,990 रुपये जमा करने के लिए। समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए और अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी से किसी अन्य राशि का दावा करने का हकदार नहीं था अपीलार्थी। अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश की तदनुसार पुष्टि की गई थी, इन संशोधनों के साथ। प्रत्यर्थी ने जिला न्यायाधीश के निर्णय का विरोध किया, उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सूत्रीकरण किया निम्नलिखित प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है:

"चाहे तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री टिकाऊ है?"

विद्वान न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष को उलट दिया और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वाद के निर्माण पर अभिनिर्धारित किया कि पुनः परिवहन का अधिकार मूल को दी गई रियायत या विशेषाधिकार था। मालिक और इसलिए न केवल इस तरह के समझौते की शर्तें होनी चाहिए सख्ती से उसके खिलाफ समझा गया, लेकिन बिक्री के लिए "सामान्य" समझौतों के विपरीत, समय अनुबंध का सार होगा। ऐसा माना जाता था कि ऐसा मालिक पुनः परिवहन का दावा करने के लिए अधिकार से पहले तर्क को सख्ती से निष्पादित करना था लागू किया जा सकता है। चूंकि, उच्च न्यायालय के अनुसार, अपीलार्थी ने समझौते के निष्पादन से पहले खतों का निपटान चाहते थे, अपीलार्थी का इरादा समझौते को उसके संदर्भ में लागू करना नहीं था और इस प्रकार वह विशिष्ट निष्पादन का हकदार नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निष्कर्षों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया,

(1) षण्मुगम पिल्लई बनाम। अन्नलक्ष्मी अम्मल, आकाशवाणी (1950) एफ. सी. 38, (2) के. सिमराथमुल बनाम। नंजलिंगैया गौडर ए. आई. आर. (1963) एस. सी. 1182, (3) हसम नूरानी मलक बनाम। मोहन

सिंह और अन्न एयर (1974) बॉम। 136 (4) एस. शंकरन (मृत) और 4
अन्य। बनाम एन. जी. राधाकृष्णन, (1994) 2 एल. डब्ल्यू. 642।

उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कानून में अस्थिर है और इसके विपरीत
है।

तथ्यों के लिए विद्वान न्यायाधीश ने यह ठहराते हुए गलती की कि
यह एक सामान्य सिद्धांत है कानून का कि बिक्री का प्रत्येक समझौता
जिसके द्वारा मूल मालिक सहमत होता है संपत्ति को वापस खरीदना ऐसे
मालिक को दिया गया एक विशेषाधिकार या रियायत है। विशेषाधिकार को
एक विशेष और विशिष्ट लाभ या लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है।
एक व्यक्ति द्वारा आनंदित, और विशेषाधिकार के रूप में एक रियायत। एक
विकल्प क्रय या पुनर्खरीद को ऐसा विशेषाधिकार या रियायत माना गया
है। [देखिए: षण्मुघम पिल्लई बनाम। अन्नलक्ष्मी, आकाशवाणी (1950)
एफ. सी. 38; के. सिमरथमुल वी. नंजलिंगैया गौडर, आकाशवाणी (1963)
एससी 1182। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक विकल्प अपनी प्रकृति से पूरी
तरह से दिए गए व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है।

" एकतरफा ", जैसा कि यह था, कि अधिकार का कड़ाई से अर्थ
लगाया गया है और" किसी पट्टे के नवीनीकरण के लिए, या संपत्ति की
खरीद या पुनर्खरीद के लिए, सभी मामलों में इस उद्देश्य के लिए सीमित

समय के भीतर सख्ती से प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा "(हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड, थर्ड एडन। वाल्युम .3 कला 281, पी 165) दूसरी ओर, बिक्री और खरीद के लिए एक समझौता, दोनों पक्षों पर दायित्वों और लाभों को लागू करने वाली एक पारस्परिक व्यवस्था है। और दोनों में से किसी एक के मामले में लागू करने योग्य है। इस तरह की व्याख्या अनुबंध पारस्परिक वादों के निष्पादन से संबंधित अनुबंध के कानूनों द्वारा शासित होगा। चाहे कोई समझौता खरीदने का विकल्प हो या "साधारण"। समझौता इसके प्रावधानों की व्याख्या पर निर्भर करेगा। कभी-कभी विकल्प स्पष्ट रूप से और शर्तों में दिया गया है। अन्य में अधिकार निहित हो सकता है। इस प्रकार जब कोई समझौता प्रदान करता है कि बिक्री प्राप्त करने का अधिकार खरीदार द्वारा कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन है, तो समझौता प्रभावी रूप से खरीद का एक विकल्प होगा, क्योंकि खरीद का अधिकार केवल द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के स्वैच्छिक प्रदर्शन पर ही प्राप्त होगा मालिक। विक्रेता खरीदार द्वारा शर्तों के प्रदर्शन के लिए मजबूर नहीं कर सकता है और फिर अनुबंध को विशेष रूप से करने के लिए नहीं कह सकता है।

इस प्रकार षण्मुगम पिल्लई बनाम अन्नलक्ष्मी, आकाशवाणी (1950) एफ. सी. 38, यह समझौते का सार था और

(iii) कि मालिक को पट्टे के तहत किशतों का समय पर भुगतान करना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर समझौता फिर से किया जाएगा। परिवहन रद्द हो जाएगा। इन प्रावधानों का अर्थ लगाया गया था और अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मूल विक्रेता को वास्तव में मंजूरी दे दी गई थी पुनः खरीद का एक विकल्प और यह हस्तांतरण के लिए एक सामान्य अनुबंध नहीं था भूमि। न्यायालय दो आधारों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा (i) खरीद पट्टे के तहत किशतों के भुगतान के अधीन थी, और एक था सशर्त अधिकार और (ii) प्रयोग के लिए एक बाहरी समय सीमा का निर्धारण अधिकार ने मूल मालिक को भुगतान करने पर फिर से खरीदने का विकल्प दिया निर्दिष्ट समय के भीतर बिक्री पर विचार। यह न केवल विवाद में था कि खरीदार पट्टे के तहत किशतों का भुगतान करने में विफल रहा था, लेकिन था समय सी को भी समाप्त करने की अनुमति दी। इस संदर्भ में न्यायालय ने कहा:

"यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि, जब कोई व्यक्ति अधिकार के लिए निर्धारित करता है कुछ शर्तों को पूरा करने पर रियायत या विशेषाधिकार की प्रकृति, एक परंतुक के साथ कि चूक के मामले में शर्त शून्य होनी चाहिए, शर्तों के अनुसार पूरा नहीं होने पर अधिकार को

लागू नहीं किया जा सकता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार।"

इसी तरह, के. सिमराथमुल बनाम में यह न्यायालय। नंजलिया गौडर, आकाशवाण (1963) एससी 1182 ने षण्मुगम पिल्लई का अर्थ लगाया और उनका अनुसरण किया, और बहुमत देखें कि:

"जहाँ एक समझौते के तहत एक विक्रेता के लिए एक विकल्प आरक्षित है उसके द्वारा बेची गई संपत्ति को फिर से खरीदने का विकल्प इस प्रकार है - एक रियायत या विशेषाधिकार और की सख्ती से पूर्ति पर प्रयोग किया जा सकता है जिन शर्तों को पूरा करने पर इसे प्रयोग करने योग्य बनाया जाता है। (जोर दिया गया)

हमारे समक्ष मामले में, अपीलार्थी का पुनः हस्तांतरण का अधिकार

संपत्ति में किसी विकल्प की कोई विशेषता नहीं है। समझौते का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है: (जहाँ प्रत्यर्थी को पहले और अपीलार्थी को दूसरे व्यक्ति में संदर्भित किया जाता है)। "2.5.1973 पर मैंने नीचे वर्णित संपत्ति खरीदी है विचार के लिए आपसे दिनांकित 2.5.1973 बिक्री विलेख का

गुण से रु. 20,000 (केवल बीस हजार रुपये) और मैं इसमें रहा हूं। उसी का अधिकार और आनंद और जबकि आपको प्राप्त करना चाहिए वर्ष, अर्थात् 3.5.1979 और आपको बिक्री के लिए भुगतान करना होगा से रु. 20,000 (केवल बीस हजार रुपये) अग्रिम राशि को कम करें से रु. 10 (केवल दस रुपये) इस दिन मुझे प्राप्त हुए। 3.5.1979 से पहले कोई भी बिक्री विचार प्राप्त करें। जबकि मैं आप नीचे उल्लिखित संपत्ति को रुपये की कीमत पर बेचने की इच्छा रखते हैं और सहमत हूँ। 20,000 आपको और मुझे रुपये की राशि प्राप्त हुई। 10 आप से बिक्री के अग्रिम विचार के रूप में।"

सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी ऐसा नहीं कर सकता था, भले ही वह तैयार और सक्षम, 3.5.79 से पहले संपत्ति वापस खरीदें क्योंकि यह बनाई गई थी अपीलार्थी द्वारा पुनः खरीद के खतरे के बिना भूमि के पांच साल के अबाधित उपयोगकर्ता को अनुमति देना। दूसरा, खंड में यह प्रावधान नहीं है कि यदि बिक्री 3 मई 1979 से पहले प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया था, अपीलार्थी हार जाएगा संपत्ति खरीदने का उसका अधिकार। समय का सार नहीं बताया गया था अनुबंध। तीसरा, दोनों में से कोई भी पक्ष अनुबंध को लागू कर सकता है जैसा कि यह था। पाँच साल बाद। इसलिए विचाराधीन समझौता एक "सामान्य" था।

बिक्री के लिए समझौता। संक्षेप में: केवल यह तथ्य कि बिक्री के लिए एक समझौते को पुनः परिवहन के रूप में वर्णित किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह पुनर्खरीद करने का विकल्प है या नहीं। क्या यह किसी भी तरह से विलेख के सार को बदल देता है। यह केवल एक रिकॉर्ड करता है।

ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जिस संपत्ति को बेचा जाना है, उसे खरीदा जा रहा था वह व्यक्ति जो मालिक हुआ करता था। कोई तार्किक भेद नहीं किया जा सकता है। पुनः खरीद के लिए एक समझौते और खरीद के लिए एक सामान्य समझौते के बीच सिर्फ इसलिए कि विक्रेता मूल खरीदार और खरीदार होता है मूल विक्रेता होता है। समझौता एक समझौता बना हुआ है कानून। मामले के तथ्यों पर आते हुए, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को पूरी राशि रु. 19,990 का भुगतान करने के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा था। समझौते में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिवादी को अच्छी तरह से यह मुकदमा भी 3 मई 1979 से पहले दायर किया गया था। आगे कुछ नहीं बचा था। समझौते के तहत अपीलार्थी द्वारा किया गया। जहाँ तक जमा की बात है

धारा 16 के स्पष्टीकरण (1) के तहत शेष राशि पर विचार का संबंध था। (ग) विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 2 के अनुसार अपीलार्थी

ऐसा करने के लिए न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर सकता है। उन्होंने ऐसा ही किया। इसलिए सभी साक्ष्यों पर विचार करने पर विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने सही निर्णय लिया।

2. स्पष्टीकरण खंड 16 (ग) के प्रयोजनों के लिए

(i) जहां किसी अनुबंध में धन का भुगतान शामिल है, वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह वास्तव में प्रतिवादी को निविदा दे या अदालत में कोई धन जमा करे, सिवाय इसके कि कब

न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्देशित; इस निष्कर्ष पर कि अपीलार्थी अपना कार्य करने के लिए तैयार और इच्छुक था समझौते के तहत दायित्व और विशिष्ट प्रदर्शन के हकदार थे यह।

उच्च न्यायालय द्वारा की गई दूसरी गलती को परेशान करने में थी कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रत्यर्थी द्वारा नहीं उठाए गए एक बिंदु पर केवल वाद के निर्माण पर तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष। यह प्रत्यर्थी का मामला न तो लिखित बयान में था और न ही विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष कि अपीलार्थी केवल इसलिए विशिष्ट प्रदर्शन का हकदार नहीं था क्योंकि उसने कथित रूप से प्रतिफल मूल्य में भिन्नता का दावा किया था। दूसरी ओर यह प्रतिवादी था जिसके पास सब कुछ था।

साथ ने इस तरह के बदलाव का दावा किया। जब अपीलार्थी ने वाद की स्थापना से पहले प्रत्यर्थी से भुगतान पर संपत्ति को पुनः संप्रेषित करने के लिए कह रु. 19,990 , यह प्रत्यर्थी का मामला था कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी को समझौते में उल्लिखित राशि से अधिक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यह रुख प्रत्यर्थी द्वारा अपने लिखित बयान में और पहली अपील पर भी दोहराया गया था। प्रत्यर्थी ने स्वयं समझौते के तहत देय बिक्री प्रतिफल की राशि जारी की थी। ऐसा करने के बाद, वह मुड़कर यह तर्क नहीं दे सकी कि यह अपीलार्थी ही था जो समझौते में बदलाव की मांग कर रहा था। वास्तव में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया कि विभिन्न ऋणों के लिए दावा पहली बार अपीलार्थी द्वारा तब किया गया था जब प्रत्यर्थी ने संपत्ति को पुनः संप्रेषित करने के लिए समझौते के बिक्री विचार के अलावा धन का दावा किया था। उच्च न्यायालय को इन परिस्थितियों में प्रतिवादी को दूसरी अपील के चरण में असंगत तर्क देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

तीसरा, यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है।

किसी भी अभिवचन में एक याचिका का अर्थ लगाने में, अदालतों को ध्यान रखना चाहिए राहत मिलती है। ऐसी अभिव्यक्ति नुकीली, सटीक, कभी-कभी अस्पष्ट हो सकती है। लेकिन फिर भी यह इकट्ठा किया जा

सकता है जो वह केवल के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है पूरे अभिवचन को पढ़कर, एक मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति के आधार पर

याचिका दायर करें। भारत में अधिकांश याचिकाओं का मसौदा वकील द्वारा तैयार किया जाता है इसलिए अभिवर्णित दलीलों का अंतर जो अनिवार्य रूप से एक से दूसरे में भिन्न होता है। अन्य। इस प्रकार, एक याचिका के पीछे सच्ची भावना को इकट्ठा करने के लिए इसे एक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए पूरा। यह किसी को अपने दायित्वों का पालन करने से विचलित नहीं करता है एक कानून के तहत आवश्यक। लेकिन यह जाँचने के लिए कि क्या उसने अपना प्रदर्शन किया है दायित्व, किसी को एक याचिका के सार और सार को देखना होगा। (सैयद 212 दस्तगीर बनाम टी. आर. गोपालकृष्ण सेट्टी, [1999] 6 एस. सी. सी. 337 341 पर) [देखें मोतीलाल जैन बनाम। रामदासी देवी, ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2408।]

हमारे समक्ष मामले में, अपीलार्थी ने किए गए समझौते को साबित कर दिया है और पक्षकारों को इसके अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं था। अपीलार्थी ने व्यक्त किया था कि भुगतान करके समझौते को पूरा करने की उसकी तैयारी और इच्छा शिकायत करें। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी करने में गलती की कि अपीलार्थी ने कभी नहीं कहा कि समझौते के तहत पुनः परिवहन के लिए विचार किया गया था जो कहा

गया था उससे कम। यह स्वीकार करते हुए कि अपीलार्थी ने केवल दावा किया था कुछ राशियों के लिए ऋण। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि वह समझौते में ही बदलाव चाहते थे। अपीलार्थी को अस्वीकार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दूसरा कारण विशिष्ट प्रदर्शन की राहत विशिष्ट राहत की धारा 20 के तहत थी अधिनियम, 1963। कोम्मिसेट्टी वेंकट सुब्बरैया बनाम पर भरोसा करते हुए। करमसेट्टी वेंकटेश्वरलू और अन्य, ए. आई. आर. (1971) ए. पी. 279 और बुचिराजू बनाम। श्री रंगा सत्यनारायण, ए. आई. आर. (1967) ए. पी. 69 उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष या पहला अपीलीय न्यायालय। इसके अलावा, पहले अपीलीय न्यायालय ने ऐसा नहीं किया था।

उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से कहा गया, यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के दावे थे झूठा है। जिला न्यायाधीश, जो तथ्य का अंतिम न्यायालय था, ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया द्वारा शेष राशि के भुगतान के प्रश्न में जाना बिक्री विलेख के तहत प्रत्यर्थी क्योंकि उसने अभिनिर्धारित किया था, और हमारे विचार में सही है कि विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में न्यायालय इस बात से संबंधित नहीं था कि क्या अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में निष्पादित मूल बिक्री विलेख के तहत कोई प्रतिफल का भुगतान किया गया था। इस संबंध में उच्च न्यायालय

द्वारा देखे गए निर्णय तदनुसार पूरी तरह से अनुचित थे। प्रतिवादी के वकील ने अंत में आग्रह किया कि अपीलार्थी को अब विशिष्ट प्रदर्शन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि भूमि की कीमत बढ़ गई थी पिछले कुछ वर्षों में खगोलीय रूप से और यह प्रत्यर्थी के साथ अन्याय करेगा कि वह उसे 1978 में निर्धारित कीमतों पर संपत्ति को फिर से देने के लिए मजबूर करे।

तर्क तर्कपूर्ण है, जहाँ न्यायालय विचार कर रहा है कि क्या या पहली बार विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री नहीं देने के लिए, जिस भूमि की कीमत में वृद्धि के बारे में सूचित करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है, वह वी. पेचिमुथु बनाम में एक प्रासंगिक कारक हो सकता है। विशिष्ट प्रदर्शन की राहत से इनकार करना। के. एस. विद्यानाडम और ओआरएस बनाम वैरवन, [1997] 3 एस. सी. सी. देखें।

लेकिन इस मामले में, विशिष्ट के लिए डिक्री प्रदर्शन पहले से ही परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है और द्वारा पुष्टि की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय। हमारे सामने एकमात्र सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय दूसरी अपील में डिक्री को उलटने में सही था। नतीजतन, के. एस. विद्यानाडम (ऊपर) में प्रतिपादित सिद्धांत लागू नहीं होगा।

पूर्वगामी कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है। हम अलग रखते हैं उच्च न्यायालय का निर्णय और प्रथम अपीलीय के निर्णय को बरकरार रखना -अदालत लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हर्षित शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |